

उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ

दांडिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या.- 2086/2026

संतबहादुर उर्फ बड़कऊ पंडा

..... आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ

.....प्रतिवादी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता	: - सचिन वर्मा
प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता	: - शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या. - 28

माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती

आवेदनकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत जमानत आवेदन अभियुक्त-आवेदनकर्ता की ओर से वाद अपराध संख्या 1/2026, अंतर्गत धारा 2/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना- गंगाघाट, जिला- उन्नाव में जमानत की मांग हेतु दाखिल किया गया है।

आवेदनकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि गैंग चार्ट में आवेदनकर्ता के विरुद्ध केवल एक मामला दर्शाया गया है, जिसमें उसे निचली न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है। जमानत आदेश, जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथ पत्र के संलग्नक-3 के रूप में अभिलेख पर उपलब्ध है। सह-अभियुक्त ननखऊ यादव उर्फ वीरेंद्र यादव को इस न्यायालय द्वारा पूर्व में ही आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 1523 /2026 में पारित आदेश दिनांक 13.3.2026 के माध्यम से जमानत दी जा चुकी है। आवेदनकर्ता उक्त सह-अभियुक्त के साथ समानता का दावा करता है। आवेदनकर्ता दिनांक 1.2.2026 से जेल में निरुद्ध है।

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदनकर्ता उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(ख) की आवश्यकताओं के अनुसार वचनपत्र प्रस्तुत करने हेतु तैयार है। आगे यह भी कहा गया है कि आवेदनकर्ता के न्यायिक हिरासत से फरार होने या गवाहों को डराने-धमकाने की कोई संभावना नहीं है। यदि आवेदनकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत के आवेदन का विरोध किया, किंतु वह आवेदनकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए उपरोक्त तर्कों एवं तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

इस तथ्य पर उचित विचार करते हुए कि आवेदनकर्ता दिनांक 1.1.2026 से जेल में है; आवेदनकर्ता को गैंग चार्ट में दर्शाए गए एकमात्र मामले में जमानत पर रिहा किया जा चुका है और जिसका विवरण जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथ पत्र में उचित रूप से दिया गया है; सह-अभियुक्त को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है; अतः मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं आवेदनकर्ता को जमानत पर रिहा करने के लिए इसे एक उपयुक्त मामला पाता हूँ।

तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

आवेदनकर्ता- संतबहादुर उर्फ बड़कऊ पंडा, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या से संबंधित है, को संबंधित न्यायालय के संतोषानुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नवत शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए, जो न्याय हित में अधिरोपित की जा रही हैं:-

- (i) आवेदनकर्ता विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदनकर्ता अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा और न ही उन्हें डराएगा-धमकाएगा।
- (iii) आवेदनकर्ता मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, ताकि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विचलित हो सके, और न ही साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा।
- (iv) आवेदनकर्ता इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन की

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

स्थिति में, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और विधि के अनुसार आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(v) आवेदनकर्ता उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(ख) की आवश्यकता के अनुसार एक वचनपत्र भी दाखिल करेगा कि वह किसी भी (अन्य) मामले में संलिप्त नहीं होगा और न ही जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा।

(vi) आवेदनकर्ता प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

(vii) यदि आवेदनकर्ता विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है तथा आवेदनकर्ता ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के अंतर्गत उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही शुरू करेगा।

(न्यायमूर्ति राजीव भारती)

मार्च 30, 2026

शुक्ला

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”